Members coming from all the States have a role to play. They should see to it and tell the State Governments that the money given by the Government of India for the rural poor to get employment, that money reaches them under various schemes.

SHRI MAHENDRA MOHAN: Sir, I am asking a very specific question. I am not making a statement. Sir, in his reply, the Minister has mentioned about the electrification of number of villages and the number of BPL households, the overall target was 21695, and the target achieved up to February, 2009 is 967, that is only 4.4 per cent. What is the target? By what time he is expecting that they will get the electrification?

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, as far as the rural electrification is concerned, I agree with the hon. Member because it had to be completed by 2009, but it did not go well because some public sector undertakings have been given the job of doing it, and there was a delay in carrying out the work. There is a thinking going on in the Government to extend the period to achieve the target that has been given here. Therefore, instead of 2009, we may go for some more time so that we are able to achieve the target of rural electrification in the country.

श्री श्रीगोपाल व्यास: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने कहा है कि राज्यों की ओर से योगदान करना चाहिए, तो जब झारखंड में प्रेसिडेंट रूल है वहां उन्होंने कितना योगदान किया है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the table which I have given, in that I have mentioned about the allocation of funds, the release of funds and the implementation by the State Government. As far as Jharkhand is concerned, Jharkhand is under the President's Rule for the last one-and-a-half months. Earlier, the elected Government was there and we persuaded the State Government to send the proposals. We received some proposals from Jharkhand for various schemes. We have not received proposals from the other State Governments and we are pursuing the matter with those State Governments so that we will be able to allocate more funds for Jharkhand, Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Bihar. All these areas which are covered by the tribal areas, the Government of India is paying more attention and more money will be provided to those State Governments.

MR. CHAIRMAN : Now, Question No. 142., Miss Anusuiya Uikey.

कोयला खानों में छत के धंसने (रूफ फाल) की घटना

†*142. **सुश्री अनुसुइया उइके**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले दिनों कन्हान क्षेत्र के छिंदवाड़ा जिले की मोआरी खान में छत के धंसने (रूफ फाल) की घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) छत के धंसने से हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है तथा इस नुकसान की लागत कितनी है;

(घ) क्या ऐसी घटनाओं की संभावना का पता लगाने अथवा इसकी चेतावनी देने की कोई व्यवस्था नहीं है और क्या इस प्रकार की घटनाओं को रोक पाना संभव नहीं है; और

†Original notice of the question was received in Hindi.

(ङ) छत के धंसने (रूफ फाल) की इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम क्या है जिसके द्वारा इसका पूर्व में ही पता लगाकर इसकी रोकथाम का प्रयास किया जाना चाहिए था और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) से (ङ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हाल में कन्हान क्षेत्र में छिंदवाड़ा जिले की माओरी खान में छत गिरने की कोई दुर्घटना नहीं घटी है।

(घ) टेल-टेल्स, जो रूफ स्ट्राटा में किसी बेड सेपरेशन का पूर्व संकेत देती है, का प्रयोग करके माओरी खान में छत गिरने की घटना की संभावना का आकलन करने के लिए पर्याप्त चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गई है। तथापि, अप्रत्यक्ष फिसलन का पूर्वानुमान लगाना कठिन है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

Incident of roof-fall in coal mines

†*142. MISS ANUSUIYA UIKEY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an incident of roof-fall in Moari mine of Chhindwara district in Kanhan area had taken place in recent days;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the details of the losses due to this roof-fall and the cost thereof;

(d) whether there is no warning system or assessment of possibility of such incidents and whether it could not be prevented; and

(e) the official responsible for this incident who was supposed to make efforts to prevent this incident by prior assessment of the same and the action taken against him?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) As reported by Coal India Limited (CIL), there is no incidence of roof fall at Maori Mine of Chhindwara District in Kanhan Area during the recent past.

(d) Adequate warning system for assessment of possibility of roof fall incidence has been put in Maori Mine by usage of Tell-Tales which gives prior indication of any bed separation in the roof strata. However, hidden slips are difficult to predict.

(e) Does not arise in view of reply given to parts (a) to (c) above.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

सुश्री अनुसुइया उइके : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो उत्तर दिया है, इस उत्तर से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यह अपने आप में अपूर्ण है। माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि कन्हान क्षेत्र में छिंदवाड़ा जिले की माओरी खान में छत गिरने की कोई दुर्घटना नहीं हुई है, मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि जनवरी, 2008 में ही अनेकों बार Roof-fall की घटनाएं हुई हैं। जिसमें LLT machine तथा मोटर पम्प roof fall में दब गई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर यह जानकारी सही है तो इन मशीनों की लागत का कितना नुकसान उठाना पड़ा है? यह आप बताने की कृपा करें।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, hon. Member ने जब इस सवाल को पूछा था, तो उन्होंने 'recent past' कहा था, इसीलिए हमने कहा कि 'recent past' में ऐसा कोई एक्सिडेंट नहीं हुआ है। आप जो बोल रही हैं, वह बिल्कुल सही बात है। 23 जनवरी, 2008 को एक एक्सिडेंट हुआ था, जिसमें छत गिरने से एक load haul dumper दब गया था। मैम्बर जो जानना चाहती हैं, उसे रिपेयर करने में 5000 रुपये का खर्चा हुआ था। मैं उनको एक और information देना चाहता हूँ कि यह Tell-Tales वगैरह सब जगह provide किये गए हैं जिससे हमें पहले से पता लग जाए, लेकिन चूंकि geological system में कई चीजें ऐसी होती हैं जो पता नहीं लगतीं, इसलिए एक्सिडेंट हुआ था। उन्होंने जो बात कही है, वह सही है।

श्री सभापति: दूसरा प्रश्न।

सुश्री अनुसुइया उइके : माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके तहत कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कोयला खदानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है?

श्री संतोष बागड़ोदिया: जितने भी safety precautions हमारे सिस्टम में हैं, पहले तो यह समझा जाए कि roof fall क्यों होती है। Roof fall, inadequacy of support के कारण होती है, inherent weakness of the roof strata, इस तरह इसके बहुत से कारण होते हैं। इसके लिए हमने जो precautions ली हैं, Multidisciplinary Internal Safety Organisation, यह Organisation है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। Safety audit of mines by experts, यह रेगुलर काम चलता है। Replacement of conventional timber support by steel support, पहले टिम्बर का सपोर्ट होता था, उसकी जगह अब स्टील का सपोर्ट देते हैं। Formulation of Systematic Support Rule/Support Plan on the basis of geomechanical properties of roof, Rock Mass Rating, greater use of Roof Bolting, Roof Stitching and Resin-grouted roof bolts in watery seams, mechanised roof bolting machines, training and retraining, and reducing exposure of workmen by increasing mechanisation, Site Discharge Loaders, Load Haul Dumpers, Powered Support Longwall, इस प्रकार safety के इतने precautions लिये जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वर्ल्ड में जो कुछ safety के precautions लिये जाते हैं, वे हमारे Coal India के माइंस में लिये जाते हैं।

श्री आर.सी. सिंह: सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा एक्सिडेंट्स रोड का होता है और सेकंड पोजिशन माइंस की है। माइंस में जिस तरह के प्रोविजंस होने चाहिए, वे implement नहीं हो रहे हैं। अभी हाल में कई माइंस को माइनिंग इंस्पेक्टर ने बंद कर दिया है क्योंकि जो सेफ्टी प्रोविजंस इनको implement करना चाहिए था, वे नहीं किये गए हैं, जिससे हजारों टन प्रोडक्शन का loss हो रहा है। जहाँ तक माओरी खदान का सवाल है, वहाँ पर माननीय मंत्री जी को शायद मालूम होना चाहिए कि 26.10.08 को सेकंड शिफ्ट में बेल्ट कन्वेयर पर बड़ा सा कोयले का लम्प तोड़ते हुए एक लोडर उसमें फंस गया, जो लोडर की ड्यूटी नहीं होती है। अगर वहाँ safety device या अन्य कोई alternate रहता तो उसकी मौत नहीं होती। मंत्री

महोदय यह बताने का कष्ट करें कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है और safety device के लिए वे क्या कर रहे हैं?

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, जो information वह जानना चाहते हैं, मैं उनको भेज दूंगा।

श्री बनवारी लाल कंछल: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आये दिन ये खबरें मिलती रहती हैं कि फलां कोयला खदान धंस गई। मेरा पहला पश्न यह है कि क्या ऐसी कोई दूरगामी नीति बनाई जा रही है, जिससे कोयला खदानों में ये दुर्घटनाएँ न हों? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो मजदूर उसमें दब जाते हैं, मर जाते हैं, उनके परिवारों को आप क्या संरक्षण देते हैं?

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, mining operations are carried out against the forces of nature and are considered risky all over the world. There are two methods of mining, namely, open casting and underground. In open cast operations, the overlying rocks are removed and placed away followed by extraction of minerals. In such cases the mining operation is carried out under the open sky. In underground operations, the mineral is extracted through vertical shaft or in-line inclined panel followed by extraction of mineral. The operation is carried out in a confined space. The condition of roof starts changing immediately after exposure due to geo-mechanical forces. Sir, in view of this यह कहना कि माइन्स में काम नहीं होता या माइन्स का हम ध्यान नहीं रखते, यह बात सही नहीं है। यह general problem है कि जब underground mines में हम काम करते हैं तो उसमें risk ज्यादा involve होता है, उस risk को कम करने के लिए हम जितनी ज्यादा सुविधाएं दे सकते हैं, देते हैं जिनसे safety precautions चलें। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले बरसों में जितने accidents होते थे, अब उनसे बहुत कम accidents हो रहे हैं, fatal accidents भी कम हो रहे हैं।

जहां तक compensation का सवाल है, compensation as per Workers Compensation Act, 1923 हम compensation देते हैं; immediate payment for general expenses देते हैं; *ex gratia* payment of 30,000 देते हैं; Life Cover Scheme 40,000 की है; payment of gratuity on the basis of the length of service, provident fund as per Coal Mines Provident Fund Rules, encashment of Earned Leave and other dues are paid; pension as per Coal Mines Pension Scheme is paid; employment is offered to eligible kin of the deceased and in case there is no eligible person for employment, monetary compensation per month is paid; payment of special relief or *ex gratia* of Rs.5 lakhs to the direct dependent of employee who dies or permanently disabled in any mine accident arising out of and in course of employment. ये benefits हम देते हैं।

श्री सिलवियस कोंडपन: सर, कोयला खानों में कोयला मजदूरों के साथ बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमारे असम में लीडो कोयला खान में छः-सात महीने पहले मजदूर लोग दबकर मर गए थे। क्या मंत्री महोदय को इस घटना की जानकारी है, अगर जानकारी है तो इस पर क्या व्यवस्था ली गई है?

श्री संतोष बागड़ोदिया: इस घटना के बारे में हमें मालूम है। नार्थ-इस्टर्न कोल माइन्स में यह घटना घटी थी। घटना होने के बाद तुरन्त एक्शन लिया गया और काफी ऑफिसर्स इसमें involve थे, जिनकी

responsibility थी, उनके ऊपर एक्शन लिया गया, वहां का जो agent था, उस पर action लिया गया। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा है कि पहले से अब accidents बहुत कम होते हैं। A dangerous occurence leading to major accident in the 3rd shift of 3.11.2008 in Panle No. E-10/20/P-1 at Ledo Colliery of North Eastern Coalfields occurred on 4.11.2008 at about 5.30 a.m. involving injuries to 19 persons and subsequent fatalities of five workmen amongst them inflicted with burn injuries. जलने से पांच आदमी वहां मर गए थे। The ISO report observed certain lapses due to failure on the part of the local management. The agent of the mine was suspended and GM and CGM were issued show cause notices.

*143. The question (s) Prof. Alka Balram Kshairiya and Shrimati Shobhana Bhartia were absent. For answer *vide* page 27 *infra*.]

Permission for erection of surface structures in coal-bearing areas

*144. SHRI R.C. SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government is giving permission for surface structures such as airports, buildings, complexes, etc. in the coal bearing areas of the country;

(b) whether it is also a fact that unauthorized people have also occupied some of the coal belts in the country which otherwise deprive the country from extracting India's primary source of energy *i.e.* coal; and

(c) if so, the reasons behind giving permission for such structures and what rehabilitation steps Government is taking or proposes to take to rehabilitate those people who are under occupation of such land which contains coal reserves?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir. Government has not given permission for construction of surface structures which are not a part of mining activity in the coal bearing areas of the country.

(b) Yes, Sir. Some unauthorized people have constructed their houses on coal bearing land in some of the coal companies preventing coal extraction.

(c) While no permission has been given for construction of such structures on coal companies land, it is proposed to rehabilitate 23847 nos. of houses belonging to unauthorized occupants of Bharat Cooking Coal Limited's (BCCL) land under Jharia and Raniganj Master Plan addressing the issues of fire and land subsidence in old mined out areas.

The salient features of the proposed rehabilitation package is given in the Statement-I and the same has been agreed to by the State Government of Jharkhand and West Bengal.